डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 21 ● भोपाल ● 1-15 अप्रैल, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को और तेज गति दी जायेगी : श्री चौहान

सहकारिता आंदोलन से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने माना मुख्यमंत्री का आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता गरीबी दूर करने का माध्यम है। मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता आंदोलन को और तेज गति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नए क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन का हस्तक्षेप होगा। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश को बदल देंगे। सहकारी मार्केटिंग सोसायटी में भी अशासकीय प्रशासक नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा। श्री चौहान यहाँ निवास प्रांगण में एकत्र हुए जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये ये कार्यकर्ता श्री रमाकांत भार्गव को अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त करने पर श्री चौहान का आभार व्यक्त करने और उनका अभिनंदन करने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास पहुँचे थे।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों से 2000 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेंहूँ की खरीदी की जायेगी। किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता नहीं करें। उनकी हर समस्या का समाधान होगा। निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सहकारिता में प्रथम स्थान पर होगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया है। भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राजपूत, पूर्व विधायक श्री रमेश सक्सेना, सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक श्री नेमिचंद जैन, देपालपुर विधायक श्री मनोज पटेल और बड़ी संख्या में सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोग उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश मंत्री श्री रघुनाथ भाटी ने आभार माना।

श्री रमाकांत भार्गव ने अपेक्स बैंक में प्रशासक का पदभार संभाला

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग की विशेष उपस्थिति में श्री रमाकांत भार्गव ने अपेक्स बैंक में प्रशासक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, विधायक श्री विजयपाल सिंह, श्री लखन पटेल, एम.डी मार्कफेड श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, एम.डी अपेक्स बैंक श्री आर.के शर्मा, सहकारिता क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मंत्रिपरिषद् का निर्णय

अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में **23 मार्च, 2018 को हुई।** मंत्रि-परिषद की बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2018 से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2018 करने की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की वर्तमान योजना के तहत सहकारी बैंको के लिए बेस रेट पूर्व वर्षो की भांति 11 प्रतिशत यथावत रखने का निर्णय लिया।

किसान अपनी आय बढ़ाने के लिये खेती के साथ पशुपालन भी अपनाएं

राज्यपाल श्रीमती पटेल से गुजरात के किसान प्रतिनिधि मंडल की सौजन्य भेंट

भोपाल। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मध्यप्रदेश में क्रियान्वित आत्मा प्रोजेक्ट में भाग लेने आये मेहसाना (गुजरात) के 50 किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने किसानों से कहा कि आत्मा प्रोजेक्ट से जो सीखा है, उसका स्वयं क्रियान्वयन करें और दूसरे किसान भाइयों को भी समझाएं।

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिये अब पशुपालन और अन्य कारोबार पर भी ध्यान केन्द्रित करें। कृषि पर आधारित उद्योगों को अपनायें। श्रीमती पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में पानी की कमी के बावजूद किसान खेती और इससे जुड़े कारोबार के जरिये अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने किसानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ** नारे पर अमल करें।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसान श्री जिगनेश चौधरी ने राज्यपाल को आत्मा प्रोजेक्ट के अध्ययन बारे में अपने अनुभव बताये। प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर, इंदौर और देवास का दौरा किया तथा वहां किसानों द्वारा खेती के साथ-साथ अन्य कारोबार अपनाकर आमदनी बढ़ाने के प्रयासों का अध्ययन किया।

मुख्यमंत्री ने दिए लहसुन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने के निर्देश

लहसुन उत्पादक किसानों से योजना में शीघ्र पंजीयन कराने की अपील

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन के गिरते भाव पर चिंता व्यक्त करते हुए लहसुन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिये प्रमुख सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास को लहसुन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने लहसुन उत्पादक किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिये शीघ्र ही अपना पंजीयन करवायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में लहसुन के गिरते भाव की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि को निर्देश दिये कि तत्काल प्रभाव से भावांतर भुगतान योजना में लहसुन उत्पादक किसानों का पंजीयन शुरू किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि लहसुन का भाव प्रदेश की राज्य स्तरीय समिति द्वारा तय किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लहसुन उत्पादक जिलों में आज से ही पंजीयन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लहसुन की फसल के लिये उज्जैन संभाग के सभी जिलों और इंदौर, राजगढ़, सीहोर तथा सागर जिलों को भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया गया है।

भावांतर भुगतान योजना में अब तक 8 लाख से अधिक किसानों ने करवाया पंजीयन

पंजीयन के लिये आयोजित की जा रही हैं विशेष ग्राम सभाएँ

भोपाल। प्रदेश में रबी फसलों के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके लिये प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा भी आयोजित की जा रही हैं। रबी फसल में चना, मसूर, सरसों, प्याज और लहसुन के लिये किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। अब तक 8 लाख 26 हजार 771 किसानों का भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन किया जा चुका है। यह पंजीयन 18 लाख 44 हजार हेक्टेयर भूमि की फसल के लिये किया गया है।

प्रदेश में लहसुन में 20 जिलों में भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन किया जा रहा है। लहसुन फसल के लिये नीमच, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, सागर, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, शाजापुर, राजगढ़, छतरपुर, आगर-मालवा, गुना, धार, देवास, सीहोर, रीवा, सतना, भोपाल और जबलपुर जिले में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। ग्रामसभाओं में पंजीयन का कार्य ऑफलाइन किये जाने की व्यवस्था की गई है।

भावांतर भुगतान योजना में इंदौर संभाग में 69 हजार 723, उज्जैन संभाग में एक लाख 57 हजार 622, ग्वालियर में एक लाख 38 हजार 946, चम्बल संभाग में 37 हजार 559, जबलपुर संभाग में 62 हजार 301, नर्मदापुरम संभाग में 34 हजार 348, भोपाल संभाग में एक लाख 72 हजार 718, रीवा में 22 हजार 32, शहडोल संभाग में 3 हजार 146 और सागर संभाग में एक लाख 30 हजार 376 किसानों के पंजीयन किये गये हैं। भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन का कार्य 3 हजार 500 कृषि साख सहकारी समितियों और 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में भी किया जा रहा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन के संबंध में जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

उपार्जन केन्द्र स्तर से किसानों को एसएमएस खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों को उपार्जन केन्द्र पर किस दिन पहुँचना है इसका एसएमएस अब किसानों को उर्पाजन केन्द्र स्तर से किया जायेगा। खाद्य आयुक्त द्वारा इस व्यवस्था के संबंध में सभी उर्पाजन केन्द्र प्रभारियों को और समितियों को निर्देश दिये गये हैं।

खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि पहले केन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को एसएमएस किये जाते थे। अब उर्पाजन केन्द्र प्रभारी, समिति किसानों को चिन्हित करेंगी और किसानों को एसएमएस किये जायेंगे। उर्पाजन केन्द्र प्रभारियों को कहा गया है कि इस बात ध्यान रखे कि उर्पाजन केन्द्र पर गेहूँ उपार्जन के लिये उतने ही किसानों को संबंधित दिन पर पहुँचने के लिये एसएमएस भेंजे जिन का वह व्यवस्थित और असानी से उपार्जन कर सकें। किसानों को परेशानी नहीं हो।

प्रदेश को लगातार पांचवीं बार मिला कृषि कर्मण पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा ● मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पुरस्कार ग्रहण

भोपाल। मध्यप्रदेश को वर्ष 2015-16 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में कृषि उन्नत मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार वितरित किया। मध्यप्रदेश का पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रहण किया। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र, ट्राफी और दो करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की गयी। मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार दस लाख टन से अधिक गेहूँ के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश को लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2014-15 में मध्यप्रदेश को कुल खाद्यान्न की श्रेणी में तथा वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015-16 में गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया।

साथ ही सेन्ट्रल जोन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के दतिया जिले को उन्नत खेती और समग्र विकास के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदेश के तीन जिले आगर-मालवा, सिंगरौली और अलीराजपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास रिमोट से किया गया। प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के दो किसान जिला होशंगाबाद के पन्नारी गाँव की श्रीमती अरूणा जोशी को प्रति हेक्टेयर 104.60 क्विंटल और जिला नरसिंहपुर के कनवास गाँव के श्री नरेश पटेल को प्रति हेक्टेयर 99.8 क्विंटल गेहूँ उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया।

प्रदेश में गेहूँ उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि

मध्यप्रदेश में गेहूँ उत्पादन के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में गेहूँ का उत्पादन 73 लाख 27 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 219 लाख 18 हजार मीट्रिक टन हो गया है। गेहूँ की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 18.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 34.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। प्रदेश ने गेहूँ उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश के शरबती गेहूँ और डयूरम गेहूँ ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश का शरबती गेहूँ देशभर में प्रसिद्ध है।

प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक

मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर में पिछले पाँच वर्षों में 18 प्रतिशत रही है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश में किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुनी करने के लिये रोड-मेप तैयार कर लिया गया है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, सिंचाई विस्तार, रेशम, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग ने रोड-मेप पर कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश बीज प्रमाणीकरण के मामले में भी श्रेष्ठ स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में 40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पैदा किया जा रहा है।

किसान हितैषी निर्णयों का परिणाम है कृषि कर्मण अवार्ड

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में पिछले 14 वर्षों में किसानों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। इन निर्णयों की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में प्रदेश में 7 लाख 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, जिसका रकबा वर्ष 2016-17 में बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 88 लाख किसानों को निःशुल्क स्वाईल हेल्थ कार्ड बाँटे गए। मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है। जिसके प्रत्येक विकासखण्ड में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की लागत से 265 प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण के अर्न्तगत दो हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन सेंटर की तर्ज पर ग्रामीण युवाओं के लिए कस्टम प्रोसेसिंग एवं सर्विस सेंटर की योजना जल्दी ही प्रारंभ की जा रही है।

शून्य प्रतिशत पर फसल ऋण

किसानों को कृषि ऋण वर्ष 2004-05 में 18 प्रतिशत की दर से दिया जाता था, जिसे वर्ष 2016-17 से 0 प्रतिशत से भी कम की दर पर दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 11 हजार 941 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया गया है।

भावांतर भुगतान योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मंडियों में भाव के उतार-चढ़ाव से होने वाले हानि से सुरक्षित करने के लिए खरीफ 2017 में 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर पर भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। योजना में 15 लाख किसानों द्वारा 28 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पाद का विक्रय मंडियों में किया जा चुका है। वर्ष 2017 में अक्टूबर से दिसम्बर के 10 लाख 50 हजार पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में 1512 करोड़ की भावांतर की राशि जमा करवाई गई है। योजना को रबी 2017-18 में भी निरंतर रखा जायेगा। रबी के लिए चना,मसूर,सरसों, प्याज और लहसुन को शामिल किया गया है। योजना में लाइसेंसी गोदाम में भण्डारण पर कुल भण्डारित मात्रा का 25 प्रतिशत भुगतान एवं उस पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना रबी 2016-17 में गेहूँ और खरीफ 2017 के धान उपार्जन करने वाले 9 लाख किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। इस पर 1700 करोड़ की राशि खर्च होंगी।

पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री गजेन्द्र शेखावत और श्रीमती कृष्णा राज, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा और कृषि संचालक श्री मोहन लाल मीणा मौजूद थे।

साइलो पर मिनटों में तुल रहीं गेहूँ की ट्रॉलियाँ

भोपाल। उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ हो गई है। जिन किसानों को एसएमएस से खरीदी की सूचना मिल रही है, वे संबंधित खरीदी केन्द्रों पर पहुँच रहे हैं। उज्जैन तहसील की 14 सहकारी संस्थाओं का गेहूँ खरीदी का कार्य ग्राम लालपुर में स्थापित साइलो पर किया जा रहा है। पचास हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले इस साइलो में किसानों की ट्रॉलियाँ मिनटों में तुल रही हैं।

ग्राम लालपुर में गेहूँ के भण्डारण के लिये साइलो की स्थापना की गई है। इस साइलो में 50 हजार मीट्रिक टन गेहूँ आधुनिक स्वचलित मशीनों से पम्पिंग द्वारा भण्डारित हो जाता है। केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल-काँटा और आधुनिक प्रयोगशाला से गेहूँ के तौल में किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही है। जैसे ही किसान ट्रॉली लेकर पहुँचते हैं, 15 मिनट में हाइड्रोलिक सिस्टम से डम्पिंग स्टेशन में गेहूँ डम्प कर तौल पर्ची लेकर घर पहुँच रहे हैं। इस साइलो की भण्डारण करने की क्षमता 150 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस व्यवस्था से एक घंटे में 50 ट्रैक्टर-ट्रॉली गेहूँ तुलकर भण्डारित भी हो जाता है।

साइलो केन्द्र में भण्डारित गेहूँ एयर-टाइट रहता है। इस कारण से इसकी गुणवत्ता भी लम्बे समय तक बनी रहती है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिये पहुँचे ग्राम बाँसखेड़ी के किसान भेरूराव, ग्राम कड़छा के किसान जाकिर हुसैन, ग्राम ब्यावरा के किसान उस्मान पटेल अपने अनुभव अन्य किसानों से भी साझा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि साइलो खरीदी में किसानों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है, जबकि पहले किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये घंटों इंतजार करना पड़ता था।

कृषक उद्यमी योजना को अन्य प्रदेशों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चैतन्य काश्यप, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कृषकों की आमदनी को बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उद्योगों की स्थापना के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक उद्यमी ऋण योजना के बारे में बताया कि इस योजना में 15 प्रतिशत सब्सिडी, सात साल तक पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। योजना में 10 लाख से दो करोड़ रूपये तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत इस वर्ष 3 हजार औद्योगिक इकाईयां स्थापित करवाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री चौहान ने बताया कि किसानों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सिंचाई साधनों का विस्तार तेजी से किया गया है। पिछले करीब डेढ़ दशक में सिचिंत क्षेत्र साढ़े सात लाख से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे 80 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जायेगा, तब राज्य का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र सिचिंत होगा। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ने के साथ ही किसान को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य ने भावांतर भुगतान योजना बनाई है। यह योजना सरकार और किसान दोनों के लिये उपयोगी है। इससे किसान को फसल का वाजिब मूल्य मिलता है और उपार्जन प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की बचत भी होती है। इस योजना के तहत अभी 25 लाख मीट्रिक टन फसल का भावांतर राशि भुगतान किया गया है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार ने मध्यप्रदेश शासन की कृषक उद्यमी योजना की सराहना की। उन्होंने इस योजना को देश के अन्य प्रदेशों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता बतायी। डॉ. कुमार ने कहा कि इस योजना का नीति आयोग द्वारा गहन अध्ययन करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सहकारी संघवाद की संकल्पना को अस्तित्व में लाने के लिये राज्य विशेष की आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। राज्यों की विशिष्टताओं के अध्ययन के लिये देश के सभी राज्यों का वे भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने आयोग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और संकल्पनाओं पर भी चर्चा की।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में मध्यप्रदेश ने अर्जित किया प्रथम स्थान

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी बधाई

भोपाल। दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो में मध्यप्रदेश ने देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इस उपलब्धि के लिये विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का संचालन किया जाता है। भारत सरकार की एजेन्सी spark द्वारा इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2018 तक मध्यप्रदेश इस योजना के सभी घटकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करा कर प्रथम स्थान पर रहा है।

इस योजना के घटकों में मध्यप्रदेश पथ विक्रेता के अर्न्तगत प्रथम स्थान पर तथा स्व-रोजगार एवं शहरी बेघरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में चौथे स्थान पर है।

जैविक खेती से आमदनी बढ़ा रहे हैं किसान

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के निरंतर प्रयासों से अब अधिकांश किसान जैविक खेती को भी अपना रहे हैं। जैविक खेती अपनाने से किसानों की आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई देने लगी है।

आगर-मालवा जिले के ग्राम खजूरी कानड़ के किसान ईश्वर राठौर ने जब से जैविक खेती अपनाई है, तब से उनकी खेती से होने वाली आमदनी में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। ईश्वर सिंह ने 8 से अधिक दुधारु पशु पाले हैं। इन पशुओं के मूत्र तथा गोबर से खाद बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने खेत में केंचुआ खाद बनाई है। ईश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने जैविक खाद तैयार कर 7 बीघा जमीन भी खरीदी है। आज उनके खेत में 7 व्यक्ति रोजगार पाकर उन्हें जैविक खाद तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं।

झाबुआ जिले में अधिकांश किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है। उन्हीं में से थांदला जनपद के जुलवानिया ग्राम के किसान कालू भी हैं। इन्हें जैविक खेती करने की प्रेरणा आत्मा परियोजना से मिली थी। इन्होंने अपने खेत में 5×10 फीट के 2 वर्मी टांका तैयार किये हैं। इसी के साथ खेत में जैविक कीट व्याधि भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिये नीम, धतूरा, करंजा और अरण्डी जैसी वनस्पति का प्रयोग कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जैविक खेती से कृषि लागत में कमी आई है और आमदनी बढ़ी है।

किसान भाई अपने दुधारू पशुओं में टैग लगवाएं

भोपाल। पशु संजीवनी (इनफॉरमेशन नेटवर्क फॉर एनीमल प्रोडक्टिवटी एण्ड हेल्थ) योजना के तहत प्रदेश में दुधारू एवं प्रजनन योग्य गौ एवं भैस वंशीय पशुओं से संबंधित समस्त जानकारी संकलित की जाकर पशुओं की पहचान हेतु पशुओं के कान में यूआईडी का टैग (बिल्ला) लगाकर पंजीयन कराया जाएगा। पंजीयन उपरांत समस्त जानकारी इनाफ सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाएगी।

समस्त पशुपालक एवं किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे अपने दुधारू एवं प्रजनन योग्य पशुओं की पहचान हेतु यूआईडी टैग (बिल्ला) अवश्य लगवाएं और दुधारू पशुओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने भावान्तर भुगतान योजना की तारीफ की

मुख्यमंत्री श्री चौहान केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिले, जी.आई. बासमती मुद्दे पर की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश में किसानों के हित संरक्षण के लिए चलाई जा रही भावांतर भुगतान योजना की मुक्त कण्ठ से तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए यह योजना एक श्रेष्ठ योजना है। अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश में कृषि के क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं का अनुसरण करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को मध्यप्रदेश को लगातार पांचवी बार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत होने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में बम्पर कृषि उत्पादन से उत्पन्न हुई समस्याओं से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि इस कारण उत्पाद की कीमतों में काफी गिरावट आई। इस कारण किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि किसानों को बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि राज्य सरकार किसानों के खाते में सीधे जमा कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री से मध्यप्रदेश में पैदा होने वाले जी.आई. बासमती चावल के मुद्दे पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि टैग ना मिलने के कारण किसानों को चावल का सही भाव नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार इस संबंध में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करे।

मुलाकात के दौरान केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वय सर्वश्री पुरुषोत्तम रूपाला और गजेन्द्र शेखावत भी मौजूद थे।

नाबार्ड स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग की कार्य योजना तैयार करें : श्री भार्गव

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की व्यापक मार्केटिंग के लिये नार्बाड कार्ययोजना तैयार करे। इसमें राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। उन्होंने यह बात नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्व-सहायता समूह पुरस्कार समारोह में कही। कार्यक्रम में वित्तीय अनुशासन और आजीविका में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के 10 महिला स्व-सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया।

श्री गोपाल भार्गव ने राज्य में स्व-सहायता समूह आंदोलन के विस्तार के लिए नाबार्ड और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप रा%य में 3 लाख स्व-सहायता समूहों से 45 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। श्री भार्गव ने बैंकों और सिविल सोसायटी संगठनों से आग्रह किया कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने नाबार्ड द्वारा बैंकों और स्व-सहायता समूहों के योगदान को रेखांकित करने और उन्हें पुरस्कृत करने की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयासों से अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को प्रदत्त 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है। साथ ही स्व-सहायता समूहों को स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल ड्रेस तैयार करने और आंगनबाड़ी केन्द्रों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने जैसे अहम काम सौंपे गये हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से तैयार की गई **सेनेटरी नेपकिन** मशीन गर्ल्स स्कूल में लगाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री के.आर. राव ने बताया कि नाबार्ड और मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलकर राज्य में 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का निर्माण किया है जिसमें से 1.25 लाख समूहों ने बैंक से ऋण भी प्राप्त किया है। इससे राज्य की ग्रामीण महिलाओं की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

कार्यक्रम में अनूपपुर, देवास, बैतूल और ग्वालियर जिले के स्व-सहायता समूहों को पुरुस्कृत किया गया। इस मौके पर श्री पी.के. जेना, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री अजय व्यास, फील्ड महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक और संयोजक, एसएलबीसी, एल एम बेलवाल, सीईओ, एम पी एस आर एल एम बैंकों के राज्य प्रमुख भी उपस्थित थे।

उपार्जन व्यवस्था
4 दिन पूर्व ही प्राप्त हो जायेगा किसान को एसएमएस

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिये समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को खरीदी केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय करने की सूचना कम से कम 4 दिन पूर्व अवश्य दी जायेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखा जायेगा कि एक ही ग्राम के लघु और सीमांत कृषकों को इस प्रकार बुलाया जायेगा कि वह आपस में समन्वय कर एक साथ वाहनों से फसल आसानी से खरीदी केन्द्रों तक ला सकें। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती नीलम शमी राव ने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं। नई व्यवस्था में किसान भाइयों को अलग-अलग तिथियों का विकल्प भी दिया जायेगा, जिसमें वे अपनी सुविधानुसार आ सकेंगे। खरीदी केन्द्रों पर किसानों की भीड़ एकत्र न हो इसलिये एक दिन में अधिकतम 20 किसानों को ही एसएमएस किये जायेंगे। कृषकों की सुविधा के लिये शेड्यूल एसएमएस की तिथि में परिवर्तन एवं शेड्यूल एसएमएस, समिति स्तर पर भी भेजे जा सकेंगे।

चना, मसूर और सरसों पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपया क्विंटल मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान का किसानों को संबोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 257 मंडियों में होगी। इन फसलों के किसानों का भावांतर भुगतान योजना में हुआ पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये लागू होगा। पंजीयन से छूट गये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। फसलों की खरीदी दस अप्रैल से 31 मई तक की जायेगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चना, मसूर और सरसों पर कृषि समृद्धि योजना में 100 रूपया प्रति क्विंटल अलग से दिया जायेगा। किसानों को सही मूल्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि खरीदी की व्यवस्था में बाधा डालने वाले तत्वों से सावधान रहें। इसमें सरकार का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर **कॉल सेंटर के नम्बर 0755 2540500 पर शिकायत** करें। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों के उत्पाद को निर्यात करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि उत्पादन के रिकार्ड बनाने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि कृषि उत्पाद का निर्यात करने के लिये एक एजेंसी बनाई जायेगी। यह एजेंसी किसानों का मार्गदर्शन करेगी। यह एजेंसी भारत सरकार से तालमेल करके वे सभी जरूरी व्यवस्थाएँ करेगी, जिससे विदेशों में भी फसलों का निर्यात हो सके।

श्री चौहान ने बताया कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना बनाई गई है। इसमें किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गेहूँ 1735 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा और सरकार 265 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देगी। समर्थन मूल्य के बाहर गेहूँ बेचने पर भी किसान को यह लाभ मिलेगा। यदि अच्छी क्वालिटी का गेहूँ दो या ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल बिकता है तब भी उन्हें 265 रूपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अच्छी गुणवत्ता का गेहूँ नहीं होने पर भी यह लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल बेचे गये धान और गेहूँ पर भी किसानों को 200 रूपया प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस साल 16 अप्रैल को पिछले साल के गेहूँ और धान के लिये किसानों के खाते में 200 रूपये क्विंटल की दर से राशि समारोहपूर्वक जमा करा दी जायेगी। **प्रदेश के किसानों के लिये 16 अप्रैल आनंद का दिन** होगा। इस दिन नया इतिहास बनेगा। उन्होंने कहा कि इस साल बेचे जाने वाली गेहूँ की फसल की प्रोत्साहन राशि 265 रूपया प्रति क्विंटल की दर से 10 जून को किसानों के खाते में आ जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले किसानों को अपनी फसल के लिये ऊँट के मुँह में जीरा बराबर राहत मिलती थी। अब 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान पर सिंचित जमीन पर राहत राशि को दोगुना करके 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की राहत मिल रही है। फसल बीमा योजना का लाभ भी अलग से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों को मिलाकर किसानों को जितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो जायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये सात हजार रूपया फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है जिसके लिये सरकार 36 हजार रूपये प्रति वर्ष देती है। किसानों को समय से पहले खाद का उठाव करने पर ब्याज की राशि भी दी जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण लौटाने की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रूपये सूखा राहत में और इतनी ही राशि फसल बीमा में देने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और भावांतर भुगतान योजना उपलब्ध है। इन दोनों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूँ के साथ चना, सरसों और मसूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खदीदा जायेगा। भावांतर भुगतान योजना में ये फसलें नहीं रहेंगी। इस योजना में लहसुन और प्याज की खरीदी की जायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि लहसुन का बंपर उत्पादन होने से भाव गिर गये हैं। लहसुन के लिये 3200 रूपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित की गई है। यदि प्याज का भाव 800 रूपया प्रति क्विंटल से कम आता है, तो प्याज की खरीदी भी की जायेगी। पिछले साल भी प्याज खरीदी गई थी।

डोडा चूरा खरीदा जायेगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदसौर, नीमच और रतलाम के अफीम उत्पादक किसानों से पारदर्शी व्यवस्था बनाकर डोडा चूरा खरीदा जायेगा और सरकार उसे जलायेगी। किसान का नुकसान नहीं होने देंगे।

30 हजार नौजवानों को मिलेगा लोन

श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना में 1900 करोड की राशि खरीफ की फसलों के लिये किसानों को दी गई है। किसानों को ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने **मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना** की चर्चा करते हुए कहा कि 30 हजार नौजवानों को इस वित्तीय वर्ष में फूड प्रोसेसिंग से जुडे रोजगार के लिये लोन उपलब्ध करवाये जायेंगे। सरकार लोन की गारंटी लेगी और 15 प्रतिशत सबसिडी देगी। सात साल तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इन युवा उद्यमियों को मूल्य संवर्धन के लिये परामर्श और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

बासमती के जीआई रजिस्ट्रेशन के लिये केन्द्र से चर्चा

श्री चौहान ने कहा कि बासमती चावल के जीआई रजिस्ट्रेशन के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु से चर्चा हुई है। प्रदेश से बासमती चावल का तीन हजार करोड का एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि बासमती चावल उत्पादक किसानों की लड़ाई सरकार लड़ रही है और संबंधित एजेसिंयों के समक्ष सभी तथ्यों को रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ पर 265 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि देने से किसानों को 26 सौ करोड़ रूपये मिल रहे हैं। पिछले साल के 200 रूपये प्रति क्विंटल देने के फैसले से 1750 करोड़ रूपये किसानों को मिलेंगे। फसल बीमा योजना में 6000 करोड़ रूपये से ज्यादा के दावे हैं। सूखा राहत का पैसा भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में किसानों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने प्रदेश को लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलने का श्रेय किसानों की अथक मेहनत को देते हुए उन्हें बधाई दी।

सौभाग्य योजना से 11 लाख गरीब परिवारों के घर पहुँची निःशुल्क बिजली

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 11 लाख 20 हजार 83 गरीब परिवारों घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। योजना में 35 लाख घरों को आगामी अक्टूबर तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जहाँ वर्षों से रोशनी नहीं थी। इसके लिये क्रियान्वित की जा रही सहज बिजली हर घर **सौभाग्य योजना** के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समुचित प्रयास कर ऐसे सभी अंधेरे में डूबे घरों को बिजली कनेक्शन सहजता और सरलता से उपलब्ध करवाकर उनके घर रोशन किये जा रहे हैं।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीनों विद्युत वितरण कम्पनी, क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभियंता और कार्मिक पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, ताकि इस योजना का लाभ बिजली विहीन परिवार तक पहुँच सके। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कम्पनी ने अब तक 3 लाख 60 हजार 632 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 4 लाख 80 हजार 934 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण वितरण कम्पनी ने अपने क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 189 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 लाख 78 हजार 517 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये हैं।

प्रदेश में 15 जुलाई को लगाये जायेंगे 7 करोड़ पौधे - मुख्यमंत्री

बान्द्राभान में पंचम नदी महोत्सव का हुआ शुभारंभ

भोपाल। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में पंचम नदी महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि जब तक हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक देश में जल की समस्या समाप्त नहीं होगी। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए काम करना होगा। श्री गडकरी ने कहा कि पृथ्वी का 70 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है। इसके नियोजन के लिये देश में 30 परियोजनाएँ बनाई गईं हैं। श्री गडकरी ने बताया कि केन्द्र शासन गंगा प्रोजेक्ट में साढ़े पांच लाख करोड़ रूपये के कार्य करवाएगा। उन्होंने बताया कि नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये पानी पर चलने वाली बस और हवाई जहाज खरीदे गये हैं।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि 5 वर्ष पहले टायलेट का पानी शुद्ध करके विक्रय कर 18 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया था। इस वर्ष 78 करोड़ रूपये का पानी विक्रय करने का लक्ष्य है। सीवरेज जल से मिथेन गैस निकालकर गंगा नदी पर बस चलाना आरंभ किया गया है। उन्होंने ग्राम एवं जिला पंचायत में सड़क निर्माण में डामर के साथ 8 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि समुद्र का पानी भी शुद्ध करके पेयजल के रूप में बेचा जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि नदी महोत्सव से प्राप्त चिंतन और सुझाव पर भारत सरकार अमल करेगी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नदी एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिये किये जा रहे विशेष कार्य सराहनीय हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नदी संरक्षण के लिये गत वर्ष नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। पाँच माह 5 दिन तक चली इस यात्रा से लोगों में नदी, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृति आई है। श्री चौहान ने बताया कि दो जुलाई 2017 को प्रदेश में 6 करोड़ 63 लाख पौधे लगाये गये, जिनमें से 80 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2018 को पुनः 7 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे और प्रदेश की 313 नदियों पर श्रमदान कर उन्हें पुनर्जीवित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य भी होगा। नर्मदा किनारे 20 जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। नर्मदा के किनारे के गाँवों में मुक्तिधाम, पूजनकुण्ड और क्षेत्र को नशामुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई संसाधनों में वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश में गेहूँ, चना, उड़द, प्याज, लहसुन आदि का भरपूर उत्पादन हुआ है। इनकी खपत के लिये प्रसंस्करण केन्द्र बनाने पर कार्य किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि जैविक खेती का अभियान नर्मदा तट से शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान हुए चिंतन के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जायेगी।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. श्री अनिल माधव द्वारा लिखित पुस्तक नर्मदा परिक्रमा मार्ग का विमोचन किया। इस अवसर पर सतगुरू जग्गी वासुदेव द्वारा नदी महोत्सव पर दिये गये संदेश का प्रसारण भी किया गया।

कार्यक्रम को सह-सरकार्यवाहक श्री सुरेश सोनी और स्वामी परमात्मानंद ने भी संबोधित किया। सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष विजेश लूनावत, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम और श्री प्रदीप पाण्डे, विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री सरताज सिंह भी मौजूद थे।

खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं किसान

भोपाल। प्रदेश में किसान खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिये आधुनिक कृषि यंत्रों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि भी दिखाई देने लगी है। किसान अब खेती से जुड़े अन्य सहायक व्यवसायों को भी अपना रहे है।

सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम राला में लगभग तीन एकड़ सिंचित भूमि पर खेती करने वाले किसान भगवत सिंह पवार बताते हैं कि उनके द्वारा लम्बे समय से बोनी के दौरान किराये पर सीडड्रिल का उपयोग किया जाता रहा है। इसके लिये उन्हें किराये के रूप में अच्छी-खासी राशि खर्च करना पड़ती थी। कई मौकों पर तो सीडड्रिल समय पर भी नहीं मिल पाती थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तो अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदी योजना की जानकारी मिली उन्होंने भी इस योजना में सीडड्रिल यंत्र खरीदा। तो उन्हें 15 हजार रूपये की अनुदान राशि भी मिली। आज भगवत सिंह सीडड्रिल मशीन से खेत में अच्छी तरह से बोनी कर पा रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

भोपाल जिले में किसान तीरथ सिंह, ग्राम बीजापूर को राज्य सरकार के कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय के मैदानी कर्मचारियों ने खेत में कृषि यंत्रों का उपयोग करने की सलाह दी। तो इन्होंने खेत में रिवर्सिबल प्लाऊ से गहरी जुताई करवाई। रोटावेटर से खेत की तैयारी की, स्पाइरल ग्रेडर और बीज का उपचार कर सोयाबीन और धान की फसल ली। तीरथ सिंह ने तीन एकड़ में सोयाबीन और दो एकड़ में धान की बोनी की। आधुनिक तौर तरीकों से खेती करने पर उन्होंने 3 एकड़ में 17 क्विंटल सोयाबीन तथा दो एकड़ क्षेत्र में 40 क्विंटल धान की पैदावार ली है। तीरथ सिंह बताते है कि आधुनिक यंत्रों से खेती करने पर उनका उत्पादन बढ़ा है और खेती की लागत में भी कमी आई है। वे अब दूसरे किसानों को भी आधुनिक यंत्रों से खेती करने की सलाह दे रहे हैं।

छतरपुर जिले के विकासखण्ड बिजावर के ग्राम पनागर के किसान धीरेन्द्र चौरसिया एक हेक्टेयर जमीन में सोयाबीन, गेहू एवं उड़द की खेती परम्परागत तरीके से करते आ रहे थे। इससे होने वाली आमदनी से उनका परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजर-बसर कर पाते थे।

झाबुआ जिले के ग्राम पारा की बैंक सखी बनी संगीता डामोर

भोपाल। झाबुआ जिले के रामा ब्लाक के ग्राम पारा की संगीता डामोर ने मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार ऋण योजना का लाभ लेकर स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया। आज संगीता ने अपनी पहचान बैंक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर ली है। बी.ए. स्नातक संगीता ने आरसेटी स्वरोजगार संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब अपने क्षेत्र में बैंक अधिकारी के रूप में कार्य करती हैं।

ग्रामीणों के बैंक संबंधी छोटे-छोटे लेन-देन का काम अब संगीता ही करती हैं। लेन-देन पर बैंक की तरफ से संगीता को कमीशन मिल जाता है और ग्रामीणों को घर बैठे बैंक की सुविधा। संगीता पहले बेरोजगार थी। गेस्ट शिक्षक के रूप में शासकीय नौकरी भी की लेकिन इतनी आय नहीं हो पाती थी, कि परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से होता। कभी-कभी तो बच्चों के स्कूल की फीस भरने का भी संकट पैदा हो जाता था।

आरसेटी स्वरोजगार संस्थान के माध्यम से संगीता का चयन बैंक सखी के रूप में हुआ। बैंक सखी का काम आगे बढ़ाने के लिये बैंक से एक लाख रूपये का लोन मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में मिला। लोन की राशि से लेपटॉप लिया, इटरनेट कनेक्शन लगवाया और कियोस्क सेन्टर चलाने के लिये आवश्यक उपकरण खरीदे। कार्य प्रारंभ करने के लिए आरसेटी संस्थान, बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। संगीता बताती है कि उसने कभी यह सोचा भी नही था कि बैंक सखी के रूप में काम करने पर उसे इतना सम्मान मिलेगा और पैसा भी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की

असंगठित श्रमिकों के लिये ऐतिहासिक योजनाएं

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्रमिकों का पंजीयन
1 अप्रैल से
7 अप्रैल तक
पंजीयन अवश्य करायें

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

असंगठित श्रमिक कौन?

कृषि मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएँ और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेन्सी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिक।

- श्रमिकों को 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली।
- गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रुपये। प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रुपये जमा किये जायेंगे।
- घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये की सहायता।
- हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान।
- स्वरोजगार के लिए ऋण।
- साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथठेला चलाने वालों को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल। बैंक ऋण की सुविधा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी।
- श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रुपये की नगद सहायता।
- श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनाएँ।

आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिक बहनों, भाइयों की बेहतरी के लिए हम संकल्पित हैं। उन्हें आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

D-83154/18 आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2018

ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में पंजीयन करवाएं और योजनाओं का लाभ उठाएं

पोर्टल shramsewa.mp.gov.in अधिक जानकारी के लिए आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से सम्पर्क करें।

असंगठित श्रमिक का कल्याण, प्रगति के अवसर मिलें समान

/CMMadhyaPradesh
/CMMadhyaPradesh

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।